**श्री सभापति:** देखिए, सवाल आपने नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था ...**(व्यवधान)**...

**श्री थावर चन्द गहलोत:** सभापति जी, बच्चों को लोन मिलता ही नहीं है, उसके लिए सिक्योरिटी मांगते हैं ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** देखिए, अगर इस पर आपको डिस्कशन करना है, तो अलग बात है ...**(व्यवधान)**...

**श्री थावर चन्द गहलोत:** सर, हम तो इसके भुक्त-भोगी हैं ...**(व्यवधान)**...

**श्री नरेश अग्रवाल:** श्रीमन्, पहले प्रश्न को तो आपने 20 मिनट दे दिए, लेकिन चूंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बारे में इतना दबाव बन रहा है ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** देखिए, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ...**(व्यवधान)**...

**श्री नरेश अग्रवाल:** आपके लिए, सभापति जी ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** नहीं, आपके लिए भी ...**(व्यवधान)**... बस प्लीज़, अब और नहीं ...**(व्यवधान)**... श्री एन.के. सिंह।

**Fiscal concessions for investment in Bihar**

*384. SHRI N.K. SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the per capita income and investment in Bihar is the lowest in the country;

(b) if so, whether Government is proposing to introduce any fiscal concessions in terms of tax breaks through excie concessions and waiver of corporate tax and customs duties to attract private investment in Bihar;

(c) if so, in what manner and by when; and

(d) if not, the alternative measures Government has in mind to overcome the development deficit?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) As per the information published by Directorate of Economics and Statistics of respective State Governments, the Per Capita Net State Domestic Product (NSDP) at current prices of Bihar was the lowest at Rs. 23435 in 2011-12, but its per capita income growth in 2011-12 at constant prices is the highest

amongst the States for which information was available. Comparable information for all States in respect of Gross Capital Formation (Investment) is not available from official sources.

(b) and (c) There is no proposal for any specific area based fiscal concession for Bihar at present.

(d) The design of fiscal transfers to States takes into account the inter-state difference in economic parameters including Per Capita Net State Domestic Product (NSDP). Many plan schemes have been designed to ensure balanced regional development and attach greater weights to lower initial conditions of the level of development of various States.

**श्री एन.के. सिंह:** माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, निश्चित ही वे इस बात से अवगत होंगे कि विकास के विभिन्न मापदंडों के अनुरूप राष्ट्रीय औसत में बिहार सबसे नीचे है। यद्यपि पिछले पांच वर्षों में उसकी काफी वृद्धि हुई है, फिर भी विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि अगर इसी रफ्तार से बिहार की प्रगति हुई, तो राष्ट्रीय औसत में पहुंचने के लिए उसे अभी तीस साल लगेंगे। इस स्थिति को देखते हुए, क्या वित्त मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि सरकार के पास क्या कुछ ऐसे निश्चित कदम हैं, जिनके आधार पर किसी सीमा तक राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य तक बिहार जल्दी ही अपनी प्रगति कर सके?

SHRI SHASHI BHUSAN BEHERA: This is related to other backward areas also. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please listen to me. ...*(Interruptions)*... Sir, this is a very serious and important subject. It is engaging my attention. The current criteria for deciding backwardness, etc., are based on terrain, population density, international borders, infrastructure backwardness, etc. I think while these criteria have served a useful purpose, it is perhaps time to revisit these criteria. I think what is important is that no State is left behind, no part of India should be left behind as we move forward. My current thinking is that we should look at the needs under different parameters.

'Per Capita' is one parameter. But there are other parameters also, like literacy, power, IMR and MMR. There may be other parameters also. But look at the mean in these parameters and measure the distance of each State from the mean; and, then, devise plans and programmes, so that those who are farthest away from the mean, come closer to the mean. This is my current thinking. I am sort of thinking

aloud in this House. It is engaging our attention. I am confident that with the support of all the sections of the House we would be able to devise a measure by which we can ensure that States, which are far away from the mean in India, are brought closer to the mean.

**श्री एन.के. सिंह**: सर, वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उन्होंने आज यहां सदन के सामने जो कहा है, उससे उन राज्यों के लिए एक नई दिशा दिखाई देती है, जो बहुत पीछे रह गए हैं। माननीय सभापति महोदय, बिहार के अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य हैं, जो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मापदंड के बहुत नीचे हैं, विशेषकर भारत के दक्षिण हिस्से में वे राज्य हैं। चूंकि अभी 14वें वित्त आयोग का गठन होने वाला है और प्रधानमंत्री ने नई पंचवर्षीय योजना की अनुमति के लिए 27 तारीख को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक बैठक बुलाई है, इसलिए क्या ये दोनों, 14वां वित्त आयोग और नेशनल डेवलपमेंट कॉउंसिल का भी प्रयोग वित्त मंत्री अपने विचार को और आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, ताकि जो उनके निश्चित विचार हैं और बहुत ही सकारात्मक विचार हैं, जिसका मैं संपूर्ण रूप से स्वागत करता हूं, क्या इनके माध्यम से भी वे अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Plan document is ready. The NDC will meet on 27th and we look forward to the NDC endorsing the Plan document. I doubt whether my thoughts can be crystallized into a plan of action before the NDC. But my thoughts will be crystallized and placed before the Fourteenth Finance Commission.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता**: मान्यवर, सरकार ने अपने जवाब में net state domestic product की जो figure दी है, उसके हिसाब से कहा गया कि बिहार की net state domestic product देश में सबसे lowest है और वह 2000 रुपए प्रति महीने से भी कम है, लेकिन बिहार स्टेट का जो sponsored propaganda है, उससे पता चलता है कि बिहार प्रोग्रेस में चीन से भी आगे चला गया है। ...**(व्यवधान)**... अमेरिका से भी आगे चला गया है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री साबिर अली**: आप अपना सवाल पूछिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति**: कृपया आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री प्रेमचन्द गुप्ता**: आपको क्या तकलीफ हो रही है? ...**(व्यवधान)**... आप अपना प्रश्न पूछिएगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री साबिर अली**: आप प्रश्न पूछिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति**: कृपया आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... Please put your question....*(Interruptions)*... No cross-talking. ...*(Interruptions)*... No cross-talking please. ...*(Interruptions)*...

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता:** आप अपना सवाल पूछिएगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री साबिर अली:** आप प्रश्न पूछिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** कृपया आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... No cross-talking ...*(Interruptions)*... No cross-talking please. ...*(Interruptions)*...

SHRI PREM CHAND GUPTA: Don't interrupt please.

**श्री सभापति:** आप अपना सवाल पूछिए, समय खत्म हो रहा है।

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता:** सर, मेरा submission यह है कि स्टेट का जो sponsored propaganda है, उसके हिसाब से बिहार ने अमेरिका से भी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री साबिर अली:** सभापति महोदय, मेरा एक objection है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** कृपया आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता:** चीन से भी आगे निकल गया है, लेकिन चिदम्बरम साहब ने कहा कि बिहार देश भर में सबसे lowest है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है? जहां तक हमारी जानकारी है, बिहार में पिछले 8-10 साल में एक सूई तक का कारखाना नहीं लगा, वहां एक मेगावाट पॉवर का additional generation नहीं हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** आपका सवाल क्या है?

**श्री प्रेमचन्द गुप्ता:** सर, मेरा सवाल यह है कि क्या सच है, स्टेट का जो propaganda है, वह सच है या चिदम्बरम साहब ने जो figure दी है, वह सच है?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am concerned and I am sure the House is concerned about the people of Bihar, the State of Bihar. I have given the facts. In terms of *per capita* Net State Domestic Product, Bihar ranks the lowest. That is unfortunate.

SHRI PREM CHAND GUPTA: It is lowest in the country.

**श्री सभापति:** प्लीज, गुप्ता जी, बैठ जाइए।

**श्री साबिर अली:** आपकी सरकार ने क्या किया? ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please listen to me. ...*(Interruptions)*... You don't want an answer; what can I do? ...*(Interruptions)*... Just a moment. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please do not bring extraneous matters into the House.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, it is the lowest. I would, respectfully, submit that it is not a matter on which we can score political points. We must be collectively sad that it is the lowest and we must look for the ways in which we can bring Bihar closer to the national average.

This is why I said that the current criteria may have served its purpose, but there are many, many States which are still very far from the mean. The mean for India in 2011-12 is Rs. 60,603 whereas in Bihar, it is Rs. 23,435. There are other States which are away from the mean. Therefore, I am saying, collectively, all of us owe responsibility to ensure that no State is left behind. Therefore, I want you to help me crystallize our thinking, devise new measures of backwardness and devise new plans and programmes by which the more backward States are brought closer to the national average. For this, we must have a collective effort rather than score political points.

**प्रो. अनिल कुमार साहनी:** सभापति महोदय, अभी जो बात उठी है बिहार में विकास के सम्बन्ध में ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** देखिए, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से सवाल पूछिए।

**प्रो. अनिल कुमार साहनी:** जिस प्रकार से अपने संसाधन से बिहार का विकास हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... गुप्ता जी, पहले मेरी बात तो सुनिए। आपका भी शासन रहा था, आपने क्या किया? ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** आप सवाल पूछिए। अगर आपको सवाल नहीं पूछना है तो बैठ जाइए।

**प्रो. अनिल कुमार साहनी:** सर, हमारा सवाल एक ही है कि जो निचले स्तर पर है, क्या उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पूरे देश में नया नियम बनाने का आपके पास कोई प्रावधान है या नहीं?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, frankly, I don't believe in these catchy phrases. Just by calling a State 'a Special Category State', nothing will happen. What is important is to have a true measure of backwardness under different parameters and devise plans and programmes and provide funds, so that under each parameter, the State which is farthest from the mean comes closer to the national average. That is the way to go about it. Please help me devise such a criterion.

**श्री राम कृपाल यादव:** सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछड़े राज्य के मापदंड को तय करने के लिए सरकार सक्षम है या एन.डी.सी. सक्षम

है? अभी जो मानक है विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, स्वयं में प्रधान मंत्री जी सक्षम हैं या उस पर एन.डी.सी. से मुहर लगाने की जरूरत है?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the current criteria, as I said, are hilly and difficult terrain, population density, share of the tribal population and the non-viable nature of State finances. Then, there is industrial backwardness. These are the criteria by which we have categorised certain States as "Special Category States" and given certain benefits. But, as I said, these criteria may have served their purpose for the time they were in force. But I think the time has come to revisit these criteria, look at each State on the basis of number ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, he wants a one-word answer. I am very happy to give a one-word answer. I will say, Sir, that the answer is, the Government can lay down the criteria.

**Poor education among tribals**

*385. SHRI BAISHNAB PARIDA: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) based study ha painted a poor picture of education among tribal community students in the country;

(b) whether it shows that Adivasis in India receive low-cost, poorest-quality and indifferently administered education in India;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether this community still continues to be marginalized in education and other Human Development Index (HDI) sectors; and

(e) if so, the details thereof alongwith an action plan to address this issue at the earliest?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) to (c) A report by the National Institute of Advanced Studies (NIAS), Bangalore, financially supported by UNICEF, New Delhi titled 'The Education